SHODH SAGAR®
Innovative Research Thoughts
ISSN: 2454-308X | Vol. 10 | Issue 3 | Jul - Sep 2024 | Peer Reviewed & Refereed

15वीं लोकसभा चुनावों का संदर्भ में विश्लेषण का अध्ययन

Devendra Bharti
Jiwaji University Gwalior

Dr. Dk Singh
Govt KRG Pg Autonomous College, Gwalior

DOI: https://doi.org/10.36676/irt.v10.i3.1470
Published: 05/09/2024

*** Corresponding author**

सार

भारत के 2009 के 15वें लोकसभा चुनावों में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावी गतिशीलता देखी गई। 543 सीटों में से 206 सीटों पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) सबसे बड़ी पार्टी थी और उसने प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथ गठबंधन सरकार बनाई। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद, भाजपा ने पिछले चुनावों की तुलना में सिर्फ़ 116 सीटें जीतीं। वाम मोर्चा, विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), ने इस चुनाव में विधायी शक्ति खो दी। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी (SP), और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) जैसे क्षेत्रीय समूहों ने अलग-अलग राज्यों में राजनीति को आकार दिया। चुनाव विशेष रूप से उच्च मतदाता भागीदारी और युवा मतदाताओं के बढ़ते प्रभाव के लिए उल्लेखनीय थे। नरेगा और किसान ऋण माफ़ी जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कांग्रेस के अभियान ने आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया, जिससे उसे जीतने में मदद मिली। 2008 के मुंबई हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देने से भी मतदाताओं की पसंद प्रभावित हुई, तथा कांग्रेस को संकट के समय में अधिक स्थिर और भरोसेमंद सरकार के रूप में देखा गया।

मुख्यशब्द: लोकसभा, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

परिचय

समाज के इस विशेष अंक में प्रस्तुत अधिकांश शोधपत्र जुलाई 2009 में नई दिल्ली में सेंटर डे साइंसेज ह्यूमेन्स द्वारा आयोजित कार्यशाला का परिणाम हैं। तब तक 2009 के आम चुनावों के परिणामों पर काफी हद तक टिप्पणी की जा चुकी थी। इसलिए कार्यशाला का उद्देश्य चुनावी परिणामों पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि विशेषज्ञों द्वारा उन शोधपत्रों पर चर्चा करना था, जो चुनावों को राजनीतिक गतिशीलता के विश्लेषक के रूप में देखते हैं, जिसका अध्ययन अधिकांश लेखक आम तौर पर अधिक सामान्य समय में करते हैं।1 जैसा कि बटलर, लाहिड़ी और रॉय (1995: 5) ने कहा, 'प्रत्येक चुनाव इतिहास में एक संभावित मोड़ होता है और एक समकालीन घटना के रूप में पूर्ण अध्ययन का हकदार

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

होता है, राजनेताओं और पार्टी संगठनों को पूरी तरह से देखने, प्रेस और प्रसारण के प्रभाव की जांच करने और आम नागरिकों की भागीदारी का आकलन करने का अवसर।'

वास्तव में समय के साथ चुनाव अध्ययनों को पढ़ने से पता चलता है कि कैसे चुनाव भारत की राजनीतिक प्रणाली के विश्लेषण में मील के पत्थर के रूप में काम करते हैं।2 प्रत्येक प्रमुख चुनावी परामर्श व्याख्याओं को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है जो राजनीति के विकास में भी योगदान देता है। इस प्रकार चौथे चुनाव (1967) ने राज्यों में कांग्रेस के प्रभुत्व के अंत को चिह्नित किया; आठवें चुनाव (1977) ने केंद्र में कांग्रेस के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया; दसवें (1996) और अधिक निर्णायक रूप से बारहवें चुनाव (1998) ने गठबंधन के युग की शुरुआत का संकेत दिया। चुनाव, घटनाओं के रूप में, चल रही प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं और कुछ प्रमुख बदलावों को उजागर करते हैं, जबकि वे दूसरों को मिटा देते हैं।

इस अंक में अधिकांश लेखकों द्वारा चुने गए वृहद परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य लोकसभा, यानी भारतीय संसद के निचले सदन के 15वें चुनाव को संदर्भ में रखना है, ताकि विभिन्न अभिनेताओं द्वारा, विभिन्न जनता के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के साथ वोट की व्याख्याओं के इस उत्पादन को उजागर किया जा सके।

राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा चुनाव परिणामों की व्याख्या

एक संभावित दृष्टिकोण यह है कि चुनावों को उस तरह से देखा जाए जिस तरह से चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा उनकी व्याख्या की जाती है। चुनावी परिणामों और रुझानों के विश्लेषण में अर्थ की खोज मतदाताओं के इरादों की व्याख्या पर बहुत अधिक निर्भर करती है, चुनाव से पहले और बाद में। जो लोग इन इरादों को समझना चाहते हैं, वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हैं, उम्मीदवार स्वयं, विजेता और हारने वाले दोनों। विजेताओं के लिए, आगे रहने के लिए उनकी ताकत का सटीक आकलन करने की आवश्यकता होती है, जबकि जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए उन निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में सुराग होना महत्वपूर्ण है, जिन्हें जीता जा सकता है। इसके अलावा, सर्वेक्षणों के आधार पर व्याख्याएँ भी हैं, चुनाव से पहले और बाद में।3 अपने सभी विश्लेषणात्मक परिष्कार के साथ, परिणामों की व्याख्या तर्कसंगतता या तर्कहीनता के संदर्भ में समस्याग्रस्त बनी हुई है।4

जीतने वाली पार्टियों के पास राजनीतिक खुफिया जानकारी का अपना नेटवर्क होता है, और उनके पास पेशेवर विश्लेषकों की व्याख्याओं तक भी पहुँच होती है। उनका अस्तित्व उनके समर्थन आधार से प्राप्त जनादेश के सटीक आकलन और व्याख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का काम अगले दौर तक और उसके बाद भी सत्ता में बने रहना होता है।

जो पार्टी सत्ता खो देती है, वह सत्ता में वापस आने के तरीकों पर काम करने के लिए अपनी हार के कारणों पर आत्मनिरीक्षण भी करती है। यह आत्मनिरीक्षण आम तौर पर उन राज्यों से इनपुट पर

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

आधारित होता है जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और जहां उनका प्रदर्शन खराब रहा, ताकि अगले दौर के लिए एक विजयी रणनीति विकसित की जा सके। अंत में, एकल-राज्य और बहु-राज्य दलों के लिए जो खुद को गठबंधन सहयोगियों और सहयोगियों के समूह में पाते हैं, उन्हें अक्सर यह तय करना होता है कि वे खुद को सरकार में रखेंगे या विपक्ष के साथ अगले दौर के परामर्श तक, चाहे वह राज्य हो या राष्ट्रीय।5 ये गणनाएँ जटिल हैं, क्योंकि उन्हें अपने राज्य में परिणाम की व्याख्या करनी होगी और अपने स्वयं के प्राथमिक उद्देश्य यानी राज्य में सत्ता पर कब्जा करने को खतरे में डाले बिना केंद्रीय संबंधों का लाभ उठाने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी।

इस प्रकार लोकसभा चुनावों को संदर्भ में रखने का एक तरीका यह है कि उन्हें बहु-स्तरीय संघीय राजनीति में अंतर-पार्टी संबंधों के ढांचे के भीतर देखा जाए और बीच की अवधि में सार्वजनिक नीति प्रक्रियाओं पर उनके प्रभाव का आकलन किया जाए। यह स्पष्ट है कि पार्टियों द्वारा चुनावी जनादेशों का आकलन और व्याख्या, विशेष रूप से सत्ता में रहने वालों द्वारा, सार्वजनिक नीति विकल्पों पर सीधा असर डालती है। यह विपक्षी दलों और उनके द्वारा विरोध की जाने वाली नीतियों पर भी समान रूप से लागू होता है। अक्सर ऐसा होता है कि यह स्पष्ट रूप से लोकप्रिय कल्याणकारी नीतियों से राजनीतिक लाभ निकालने और साथ ही विपक्ष की भूमिका निभाने, यानी विरोध करने का एक नाजुक संतुलन बनाने का काम होता है।

8 संसदीय लोकतंत्रों में राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए सरकार-विपक्ष के संबंध महत्वपूर्ण हैं। संघीय राजनीति में यह संबंध दो स्तरों पर एक साथ चलता है, जिसमें 1971-72 में राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को अलग-अलग करने के बाद से ही कैलेंडर एक-दूसरे से टकराते रहते हैं। संघीय गठबंधन संकेंद्रित वृत्तों से मिलकर बने होते हैं और उनके निर्माण में प्रयुक्त गणनाएं चुनावी कैलेंडर और प्रत्येक वृत्त में साझेदारों और सहयोगियों की मजबूरियों से काफी प्रभावित होती हैं।

उद्देश्य

1. भारतीय और राज्य दलों के बीच लोकसभा सीटों का वितरण
2. 15वीं लोकसभा चुनावों गकी गणना का अध्ययन

राज्य के लक्ष्य, संघीय अनिवार्यताएँ

2009 के परामर्श से प्राप्त जनादेश को समझने के लिए, हमें संघीय राजनीति के दो स्तरों, राष्ट्रीय और राज्य, के परिणामों को संदर्भ में रखना होगा और दोनों के बीच संबंधों की प्रकृति को परिभाषित करने का प्रयास करना होगा। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि 15वीं लोकसभा के चुनावों को 1989 में कांग्रेस की करारी हार के बाद से पिछले दो दशकों के परिभाषित रुझानों के संदर्भ में देखा जाए। दोहरी संघीय राजनीति के स्तरों के बीच संबंधों के सुराग उन तरीकों की खोज करके उभर सकते हैं जिनसे राज्य स्तर पर चुनाव लोकसभा चुनावी जनादेश से जुड़े या अलग हुए हैं। चुनावी परामर्श कैलेंडर की निरंतर चुनौती के प्रति संघीय गठबंधनों की प्रतिक्रियाएँ, जिनके अपने आंतरिक तर्क हैं,

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

समान रूप से शिक्षाप्रद हैं। अंत में, संघीय गठबंधनों में निर्णय लेने पर अनुभवजन्य डेटा से पता चलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार (1999-2004) द्वारा पहली बार शुरू किए गए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली पहली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार (2004-09) द्वारा आगे विकसित किए गए प्रणालीगत नवाचारों ने यह सुनिश्चित किया कि गठबंधन के सदस्यों की निर्वाचन क्षेत्र की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए और इस प्रकार सरकारी स्थिरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए।8

जबकि आंदोलनों और पार्टियों की अलग और अक्सर पहचान योग्य सामाजिक जड़ें होती हैं, वे अपनी चुनावी रणनीति और रणनीति तैयार करने में संस्थागत मापदंडों पर प्रतिक्रिया करते हैं। 1950 के दशक में मौरिस डुवर्गर (1954) और जॉर्जेस लावौ (1955) के बीच इन दो तत्वों को दिए जाने वाले सापेक्ष भार पर बहस के बाद से, राजनीति विज्ञान ने इस मुद्दे से जूझने की कोशिश की है। दलीय प्रणालियों के विखंडन की आम तौर पर स्पष्ट सामाजिक जड़ें होती हैं और भारत के मामले में, राजनीति के जातिगत स्वरूप और सांस्कृतिक बहुलवाद को देखते हुए, उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति बहुस्तरीय संघीय राजनीति के चुनावी अवसरों की संरचना द्वारा निर्धारित होती है और अक्सर निर्धारित होती है। इन गणनाओं में, तथ्य यह है कि संघीय राजनीति अपनी शक्ति और संसाधनों के वितरण में केंद्रीकृत है, जो किए गए विकल्पों पर और अधिक भार डालता है।

लोकसभा सीटों का वितरण

अध्ययन के तहत अवधि के टिकाऊ रुझानों में से एक दलीय प्रणाली के संघीकरण के परिणामस्वरूप एकल-राज्य और बहु-राज्य दलों की संख्या में लगातार वृद्धि है। 9 कोई भी विश्लेषणात्मक रूप से पहली पीढ़ी के राज्य दलों के बीच अंतर कर सकता है, जो स्वतंत्रता-पूर्व युग में या कांग्रेस के प्रभुत्व चरण के तहत पैदा हुए थे, उन राज्य दलों से जो बाद के चरण में अस्तित्व में आए। जबकि सबसे प्रमुख दल मुख्य रूप से क्षेत्रीय पहचान की राजनीति पर आधारित थे, वैचारिक विशिष्टताओं पर आधारित दल भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे (तिरिमाग्नि-हर्टिग और अरोड़ा 1972)।10 राज्य दलों की दूसरी पीढ़ी 1969-1977 के अपने अति-केंद्रीकरण चरण के दौरान कांग्रेस के क्रमिक विखंडन और अंततः पतन तथा उसके बाद अल्पकालिक जनता विकल्प के विस्फोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। ये एकल-राज्य और बहु-राज्य दल संघीय गठबंधनों के निर्माण खंड हैं, क्योंकि 1996 के चुनावों में कांग्रेस की सीट हिस्सेदारी में भारी गिरावट देखी गई थी और भाजपा इस तरह खाली हुए राजनीतिक स्थान पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। जैसा कि निम्नलिखित तालिकाओं से पता चलता है, एकल-राज्य और बहु-राज्य दलों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है।

तालिका 1. अखिल भारतीय और राज्य दलों के बीच 1996-2009 के दौरान लोकसभा सीटों का वितरण

अखिल भारतीय पार्टियाँ	11LS:1996	12LS:1998	13LS:1999	14LS:2004	15LS:2009

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

	% सीटें	% सीटें	% सीटें	% सीटें	% सीटें
कांग्रेस	25.8	26.0	21.0	26.7	37.9
भाजपा	29.6	33.5	33.5	25.4	21.4
उप योग कांग्रेस+भाजपा	55.4	59.5	54.5	52.1	59.3
राज्यीय पार्टियाँ					
बहु-राज्यीय पार्टियाँ*	18.8	11.8	13.3	14.9.	9.9
एकल-राज्यीय पार्टियाँ निर्दलीय.	25.8	28.7	32.2	33.0	30.8
उप कुल राज्य पार्टियाँ	44.6	40.5	45.5	47.9	40.7
कुल योग	100	100	100	100	100

राज्य स्तरीय दलों के बीच लोक सभा में वोट शेयर का विभाजन

तालिका 2. 1996-2009 के दौरान अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय दलों के बीच लोक सभा में वोट शेयर का विभाजन

	11LS:1996	**12LS:1998**	**13LS:1999**	**14LS:2004**	**15LS:2009**
	% वोट शेयर	% वोट शेयर	% वोट शेयर	% वोट शेयर	% वोट शेयर
अखिल भारतीय पार्टियाँ					
कांग्रेस	28.80	25.82	28.30	26.53	28.52
भाजपा	20.29	25.59	23.75	22.16	18.84
उप योग कांग्रेस+भाजपा	49.09	51.41	52.05	48.59	47.36
राज्यीय पार्टियाँ					
बहु-राज्यीय पार्टियाँ*	22.72	19.36	20.11	16.61	16.24
एकल-राज्यीय पार्टियाँ और निर्दलीय	28.19	29.23	27.84	34.80	36.40
एकल-राज्यीय पार्टियाँ और निर्दलीय	50.91	48.59	47.95	51.41	52.64
कुल योग	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

*बहु-राज्यीय पार्टियाँ वे छोटी पार्टियाँ हैं जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा लगातार चुनावों में 'राष्ट्रीय' के रूप में मान्यता दी जाती है। 2009 में ये सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, आरजेडी और एनसीपी थीं।

इन तालिकाओं को सरसरी तौर पर पढ़ने से दो तत्काल अवलोकन सामने आते हैं: (ए) राज्य दलों के संबंध में अखिल भारतीय दलों द्वारा जीती गई सीटों का अनुपात 2009 में 1998 के स्तर के समान है; और (बी) उनके संयुक्त वोट शेयर में गिरावट एक सतत प्रवृत्ति है, जो सभी पांच चुनावों में सबसे कम है। पहली नज़र में, यह 'राजनीतिक सत्ता के सामाजिक आधार में आमूलचूल परिवर्तन' नहीं है, जैसा कि 2004 के चुनावी नतीजों में पहली नज़र में लगा था। यह कहा जा सकता है कि फर्स्ट पास्ड द पोस्ट (एफपीटीपी) चुनावी प्रणाली की कार्यप्रणाली ऐसी है कि इन सभी सीमाओं के बावजूद, वोट कांग्रेस के लिए एक आरामदायक जीत में तब्दील हो गए और उसे अपने गठबंधन सहयोगियों को चुनने का विकल्प दिया।

13 हालांकि भाजपा द्वारा अपने निराशाजनक प्रदर्शन को पढ़ने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जीत के कारणों की अपनी व्याख्या सामने रखी है। यह अपने जनादेश के नवीनीकरण को अपने पहले कार्यकाल के दौरान बनाए गए समावेशन के नीतिगत ढांचे की पुष्टि के रूप में देखता है। 'यह समावेशी विकास, समान विकास और एक धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी भारत के लिए जनादेश है।'

यह जनादेश को शांति और स्थिरता की इच्छा के रूप में भी देखता है और आंतरिक सुरक्षा को नई सरकार की पहली प्राथमिकता मानता है। अगर किसी को कांग्रेस के पुनरुत्थान की व्याख्या करनी है, जो एक समय में 'कांग्रेस के बाद की राजनीति' प्रतीत होती थी, तो उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि पारंपरिक ज्ञान के दूसरे स्तंभ का क्या हुआ: सत्ता-विरोधी वोट। जिस परिकल्पना का और परीक्षण किया जाना चाहिए, वह यह है कि यह खराब आर्थिक विकास के दौर में भी अच्छी रही और यह मतदाताओं की हताशा का प्रतिबिंब था, जो यह देखने के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य विकल्प को आजमाने के लिए तैयार थे कि क्या इससे जीवन की बेहतर स्थिति मिलती है। चुनाव जनादेश के नवीनीकरण की हालिया प्रवृत्ति को जीतने वाली पार्टियों द्वारा कल्याणकारी नीतियों के उनके प्रभावी क्रियान्वयन के समर्थन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। चुनावी संदर्भ में प्रभावी आर्थिक नीति को मुख्य रूप से कीमतों को नियंत्रित रखने और बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की सरकारों की क्षमता के रूप में देखा जाता है। नौकरियों और कल्याण लाभों के प्रावधान जैसी अन्य उपलब्धियों के लिए राजनीतिक लाभ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा है।

गठबंधनों में बहुमत का प्रलोभन हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन द्वि-नोडल संघीय राजनीति में यह महत्वपूर्ण आयाम ले लेता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करने के लिए काम करने वाली पार्टियों के लिए खुद से पूर्ण बहुमत की मांग करना स्वाभाविक है, पार्टी प्रणाली का संघीयकरण

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

बहुसंख्यक पार्टियों की पकड़ को ढीला करने और राज्य की स्वायत्तता की रक्षा करने की मतदाता इच्छा को अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है।

उपसंहार

अंत में, एस. तवा लामा-रेवाल भारत में चुनाव अध्ययन के उत्पादन की स्थितियों पर विचार करती हैं। इस साहित्य की उनकी आलोचनात्मक समीक्षा विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों को रेखांकित करती है जिनका उपयोग चुनावों के अध्ययन में किया जा सकता है और किया गया है। वह चुनाव अध्ययन के एक प्रमुख ब्रांड, यानी सर्वेक्षण अनुसंधान को वित्तपोषित करने और प्रचारित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। वह इस समृद्ध घटना को समझने में मानव विज्ञान के महत्वपूर्ण, लेकिन आज काफी हद तक कम प्रतिनिधित्व वाले योगदान पर भी जोर देती हैं। उनके शोधपत्र में तर्क दिया गया है कि चुनाव अध्ययन वास्तव में विज्ञान और राजनीति के बीच में हैं, जो उन्हें संदर्भ में रखना और भी अधिक आवश्यक बनाता है - और यही वह है जिस पर SAMAJ का यह अंक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ग्रंथ सूची

1. बार्टेल्स, लैरी एम. (2008) 'द इरेशनल इलेक्टोरेट', द विल्सन क्वार्टरली, 32(4), शरद ऋतु।
2. बटलर, डेविड; लाहिड़ी, अशोक; रॉय, प्रणय (1995) इंडिया डिसाइड्स: इलेक्शन 1952-1995, दिल्ली: बुक्स एंड थिंग्स
3. डिसूजा, पीटर; श्रीधरन, ई. (संपादक) (2006) इंडियाज पॉलिटिकल पार्टीज, नई दिल्ली: सेज।
4. डुवर्गर, मौरिस (1954) पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूयॉर्क: विले।
5. फ्रेंकल, फ्रांसिन; हसन, ज़ोया; भार्गव, राजीव; अरोड़ा, बलवीर (संपादक) (2000) ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया: सोशियो-पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. लोकनीति (2009) 'राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2009', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 26 सितंबर -2 अक्टूबर, पृ. 33-205.
7. नायर, बलदेव राज (2009) सिकुड़ते राज्य का मिथक। वैश्वीकरण और भारत में राज्य। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. पलशिकर, सुहास (2009) 'एक नए और संभावित गठबंधन का संभावित उदय?' आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 23 मई, पृ. 8-10.
9. सैज़, लॉरेंस (2001) 'भारत में 1999 का आम चुनाव', चुनावी अध्ययन, 20(1), पृ. 164-169.
10. शास्त्री, संदीप; सूरी, के.सी; यादव और योगेंद्र (संपादक) (2009) भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति। 2004 में लोकसभा चुनाव और उसके बाद, दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

11. सूरी, के.सी. (2004) 'भारत में लोकतंत्र, आर्थिक सुधार और चुनाव परिणाम', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 18 दिसंबर, पृ. 5404-11।
12. सूरी, के.सी. (2007) दक्षिण एशिया में राजनीतिक दल: परिवर्तन की चुनौती, स्टॉकहोम: आईडिया।
13. तिरिमाग्नि-हर्टिग, क्रिस्टियन; अरोड़ा, बलवीर (1972) लेस पार्टिस पॉलिटिक्स इंडियंस, पेरिस: डॉक्यूमेंटेशन फ्रेंचाइज़, नोट्स एट एट्यूड्स डॉक्यूमेंटेयर्स नं. 3851-52।

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com